सांध्य दैनिक

क्राईम स्टोरी

देहरादून, बुधवार 10 जनवरी 2018 (RNI No. UTTHIN/2009/30725) वर्ष 9, अंक 136 पृष्ठ 8 1.00 रूपये

प्रकाश पांडे के मन की बात सुनकर भी

बेपरवाह रही उत्तराखण्ड सरकार!

● पीएम को मन का दर्द सुनाकर भी टूट गई पांडे की सांसे ● पीएमओ से आई शासन में चिट्ठी कहां हो गई गायब?

देहरादून। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पदभार संभालने के बाद से लगातार देशवासियों को अपने मन की बात बता रहे हैं और भाजपा सरकारें प्रधानमंत्री के मन की बातों को सुनने के लिए चौकडी भी लगाते हैं लेकिन जब उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के एक ट्रांसपोर्टर ने देश के प्रधानमंत्री को अपने मन की बात के लिए खत लिखा तो पीएमओ ने उसके मन के दर्द को सुनकर उत्तराखण्ड शासन को पत्र भी लिखा लेकिन पीएमओ के लिखे पत्र को शासन ने हवा में उडा दिया जिसके चलते ट्रांसपोर्टर ने पीएम से मन की बात कर अपनी आखिरी उम्मीद को भी टूटते हुए देखा तो उसने सरकार के सामने जहर खा लिया और उसकी सांसे आखिरी क्षण तक यही कहती रही कि आखिर उसका जो हर्ष हुआ है भविष्य में किसी और का ऐसा हर्ष न हो। हैरानी वाली बात है कि शासन के अफसर पैदल एक ईमारत से दूसरी ईमारत तक न जायें इसके लिए तो सचिवालय में लाखों रूपये की लागत से पुल बना दिया गया लेकिन एक ट्रांसपोर्टर अपने ही पैसे निकलवाने के लिए पीएम से लेकर सरकार तक को अपने मन की बात सुनाता रहा लेकिन उत्तराखण्ड की बेपरवाह सरकार को इतना समय नहीं मिला कि वह एक आहत ट्रांसपोर्टर का दर्द सुन सके?

उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी के प्रकाश पांडे ने अपनी मौत से पूर्व भाजपा प्रदेश कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तराखण्ड सरकार के मुखिया को जीएसटी व नोटबंदी को लेकर कटघरे में खडा किया था। मौत के आगोश में जाने से पहले जब प्रकाश पांडे ने प्रधानमंत्री को अपने मन की बात को लेकर खत लिखा और उस खत के लिखने के बावजूद जब उसकी आस टूट गई तो उसने मौत को गले लगा लिया लेकिन प्रधानमंत्री को जो उसने खत लिखा वह यूं लिखा गया था।

श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। विषय नोटबंदी खनन पर रोक व जीएसटी से उत्पन्न हालात।

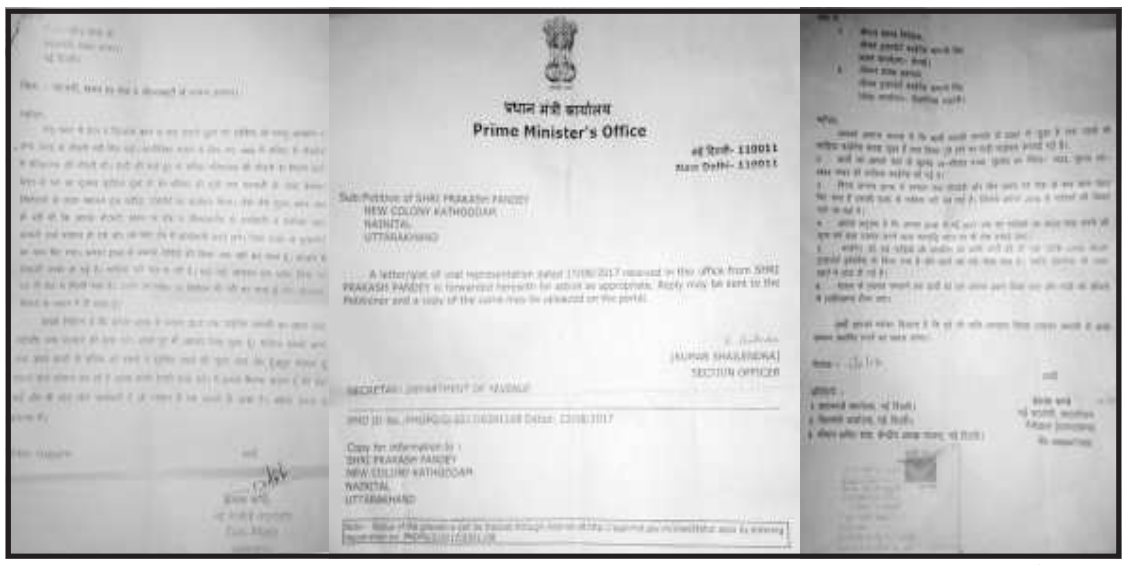

महोदय सन् 1991 में इण्टर व डिप्लोमा करने के बाद नौकरी ढूंढने की कोशिश की परंतु आरक्षण व अन्य वजह से नौकरी नहीं मिल पाई आजीविका चलाने के लिए 1998 में संविदा में रोडवेज में परिचालक की नौकरी की। शादी की, बच्चे हुये तो संविदा परिचालक की नौकरी से मिलने वाले वेतन से घर का गुजारा मुश्किल हुआ तो घर परिवार की पूंजी तथा घरवाली के जेवर बेचकर रिश्तेदारों से उधार मांगकर ट्रक खरीदा, ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया जैसे-तैसे गुजर बसर चल ही रही थी कि आपके नोटबंदी, खनन पर रोक व जीएसटी से कोराबारी ठेकेदार तथा कम्पनी वाले परेशान हो गये और हमे पैमेंट देने में आनाकानी करने लगे जिस वजह से ट्रांसपोर्ट का काम पिट गया। अगस्त 2016 से अब तक गाडियों की किस्त जमा नहीं कर पाया हूं बाजार में देनदारी काफी हो गई है। गाडियां नहीं चल पा रही हैं पाई-पाई जोडकर एक प्लाट लिया था वह भी बैंक में गिरवी रखा है अपनी जीवन बीमा की प्रिमियम भी नहीं भर पाया हूं और आज तक किराये के मकान में ही रहता हूं। आपसे निवेदन है कि अगस्त 2016 से अगस्त 2017 तक प्राईनेंस कम्पनी का ब्याज तथा ओडी मॉफ कराने की कृपा करें इससे पूर्व भी आपको लिख चुका हूं। महोदय आपसे अपने तथा अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की गुहार लगा रहा हूं बहुत परेशान हूं। कृपा करके हमारी मद्द करें मैं आपसे मिलना चाहता हूं मेरे जैसे कई और भी छोटे-मोटे कारोबारी हैं जो परेशान हैं एक आपसे ही आशा है आपके जवाब के इंतजार में।

प्रकाश पांडे के इस खत पर पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त 2017 को उत्तराखण्ड शासन को पत्र लिखा कि प्रकाश पांडे के पत्र पर एक्शन लिया जाये जो भी उचित हो और एक कापी प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल और एक कापी प्रकाश पांडे को पत्र का जवाब भेजा जाये। शासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आये इस खत को हवा में उड़ा दिया? यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद की किरण टूटने के बाद ट्रांसपोर्टर ने अपने आपको मौत के आगोश में धकेल दिया।

मजिस्ट्रेट जांच बनेगी गले की 'फांस'

आखिर सत्रह सालों में ऐसी जांच का क्या हुआ हश्र?

देहरादून। उत्तराखण्ड का जन्म हुए सत्रह साल से अधिक का समय हो गया है और जब भी राज्य में कोई बडा हादसा या दुर्घटना हुई तो उसके बाद सरकारों ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिये लेकिन इन जांचों का हश्र आज तक क्या हुआ यह सबको पता है? अब प्रकाश पांडे की मौत पर सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिये लेकिन यह जांच सरकार के गले की फांस बन सकता है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर चीख-चीखकर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके ओएसडी को लेकर अपनी नाराजगी दिखा रहा था उसके चलते कैसे कोई अफसर इस जांच को अंजाम तक पहुंचा पायेगा यह एक बडा प्रश्न सरकार की जांच पर भी खडा हो गया है और यह बात उठने लगी है कि क्या इंसान की कीमत बारह लाख रूपये है। जैसे कि सरकार ने प्रकाश पांडे की मौत के बाद उसके परिजनों को बारह लाख मुआवजा देने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि प्रकाश पांडे ने जब कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के जनता दरबार में देश के प्रधानमंत्री व उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई थी तो उसे भाजपा प्रदेश कार्यालय से बाहर कर दिया गया था। वहीं प्रकाश पांडे ने खुद वीडियो बनाकर उसने मुख्यमंत्री के ओएसडी उर्वादत्त भट्ट के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई जिससे कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ हमलावर हुई कि प्रकाश पांडे की मौत की जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये हैं लेकिन यह जांच उसके लिए भी गले की फांस बन सकता है क्योंकि जब प्रकाश पांडे ने जहर खाया था तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उसका मरने से पूर्व बयान भी दर्ज किया होगा ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिन राजनेताओं के खिलाफप्रकाश पांडे ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी क्या उनके नाम मजिस्ट्रेट जांच में अंकित करने का साहस जांच अधिकारी कर पायेंगे? यह सबको मालूम है कि अगर कोई आत्महत्या कर अपने सुसाईड नोट में किसी का नाम पीडित करने के रूप में लिखता है तो उस पर आईपीसी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही होती है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रकाश पांडे की मौत में भी मजिस्ट्रेट जांच के बाद किसी भी राजनेता के खिलाफआईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हो पायेगा? यह यक्ष सवाल राज्य के गलियारों में बार-बार गूंज रहा है।

जान की कीमत बारह लाख

सोनल चौहान की बेहद हॉट फोटोज वायरल..फैंस को इस अंदाज में किया विश

सोनल चौहान ने बॉलीवुड में कदम रखते ही धूम मचा दी थी। सोनल चौहान पहली बार जन्नत फिल्म में इमरान हाशमी के साथ नजर आई थी और उसके बाद वो फिल्म काफी बड़ी हिट हुई थी। इतनी बड़ा सफलता के बाद भी सोनल चौहान बॉलीवुड में वो मकाम नहीं हासिल कर पाई जो कि उनको मिलना चाहिए था। ये फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी तब चर्चा हो रही थी की सोनल चौहान अपने फिल्मी करियर में काफी नाम कमाएंगी। इसके बाद से अचानक सोनल चौहान गायब हो गई और फिर किसी भी फिल्म में दोबारा नजर नहीं है। हालांकि इसके बाद उनको साउथ की फिल्मों में भी देखा गया था। इन दिनो सोनल चौहान फिल से चर्चा में है दरअसल उन्होने नए साल की शुभकामनाएं अपनी हॉट फोटोज शेयर करके दी है जो कि सोशल मीडिया मे जमकर वायरल हो रही है..

दिल्ली के गार्गी कालेज से पढ़ी सोनल ने मॉडलिंग में नाम कमाया पर फिल्मों में कुछ खास ना कर सकी। मिस वर्ल्ड टूरिज्म 2005 में सोनल चौहान को मलेशिया में मिस वर्ल्ड टूरिज्म पेजेंट मिला था। आपका सुरुर इसके बाद 2006 में सोनल को हिमेश के एलबम आपका सुरुर में भी ब्रेक मिला था। बेस्ट डेब्यू एक्सट्रेस 2008 में सोनल को फिल्मफेयर ने जन्नत के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया था। साउथ में एंट्री 2008 में ही सोनल ने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होने फिल्म रेनबो के साथ शुरुआत की थी। म्यूजिक वीडियो 2017 में एक बार फिर सोनल नजर आई। ये एक म्यूजिक वीडियो था।

गजब है सुहाना खान का बेबी पिंक लुक

बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरूख खान की बेटी आये दिन किसी ना किसी कारण से सुखियों में छाई रहती हैं। आपको बता दें कि इनदिनों शाहरूख खान की पूरी फैमिली दिल्ली में एक रिलेटिव की शादी में व्यस्त है। लेकिन बेटी सुहाना अपनी कजिन की शादी में खूब मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं साथ ही उनके अलग-अलग ट्रेडिंशनल लुक्स इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस शादी के हर एक मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाल ही में सुहाना खान खूबसूरत बेबी पिंक कलर के लहंगा चोली में नजर आ रही हैं जिसके साथ सुहाना ने फ्लोवर मांग टीका लगा रहा हैं।

आपको बता दें कि सुहाना ने पिस्ता ग्रीन कलर लहंगे में दिखीं, जिसको डिजाइनर मोनिषा जासिंह ने डिजाइन किया था। इस हैवी वर्क से लहंगे की कीमत लगभग 306,356 यानी तीन लाख छ हजार तीन सौं पैंसठ है। यह लहंगा इंडियन कूट्यॉर 2017 के कलेक्शन में से हैं, जिसे मोनिषा जयसिंह ने ओपेरा कलेक्शन नाम दिया है। ग्लैमर जगत में अभी सुहाना ने कदम भी नहीं रखा है लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी काफी फैन फॉलोविंग हैं और उनकी आए दिन तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। आने वाले वक्त में सुपरस्टार बनने के लिए जो गुण होने चाहिए वह सुहाना में अभी से दिख रहे हैं।

नौशीन अली सरदार ने देश के प्रति जिम्मेदारी को समझने का प्रण लिया

हर कोई नए साल के अवसर पर अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाने के लिए कई नए प्रण ले रहा है, लेकिन अभिनेत्री नौशीन अली सरदार ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रण लिया है। नौशीन को 'कुसुम', 'बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा' और 'गंगा' जैसे शो में अभिनय कर चुकी हैं। नौशीन ने कहा,''मैंने निजी तौर पर कोई प्रण नहीं लिया। हालांकि, मैंने अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना की है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मुझे आशा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।'' अभिनेत्री ने विश्व के लिए प्रार्थना की है कि जो भी लड़ाई या संघर्ष चल रहा है, वह समाप्त हो जाए। आशा है कि हर ओर शांति हो और लोग खुश रहें।

अर्शी खान ने भी साइन की बॉलिवुड फिल्म?

कहते हैं बिग बॉस के घर आए कंटेस्टेंट्स की किस्मत बन जाती है और ताज़ा खबर घर से निकल चुकीं अर्शी खान को लेकर है।

सबसे कॉन्ट्रोवर्शल कंटेस्टेंट रहीं अर्शी

अर्शी बिग बॉस 11 की सबसे कॉन्ट्रोवर्शल कंटेस्टेंट के तौर पर देखी गई हैं, जो इस घर में एंट्री से लेकर अब तक भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

अर्शी खान ने साइन की फिल्म?

रिपोर्ट्स की मानें तो अर्शी खान ने एक बॉलिवुड फिल्म साइन की है और इस खबर को कन्फर्म किया है उनके मैनेजर फ्लिन ने।

फिनाले के बाद मिलेगी जानकारी

हालांकि, फिल्म को लेकर उन्होंने कोई अन्य जानकारी शेयर नहीं की है और कहा है कि बिग बॉस 11 के फिनाले के बाद ही फिल्म से जुड़ी जानकारियां दी जा सकेंगी।

सबसे ज्यादा सर्च की गईं अर्शी

गौरतलब है कि अर्शी 2017 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में सनी लियोनी के बाद दूसरे नंबर पर रही हैं।

विकास की सबसे चहेती रहीं

अर्शी बिग बॉस के घर में हालिया दिनों में विकास की सबसे चहेती रहीं। चूंकि विकास टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं इसलिए माना जा रहा था कि बाहर निकलने के बाद अर्शी को टीवी जगत में आसानी से एंट्री मिल जाएगी।

पहले शिल्पा शिंदे की अच्छी दोस्त थीं

वह पहले शिल्पा शिंदे की अच्छी दोस्त थीं, लेकिन घर से निकलते-निकलते दोनों के बीच खूब लड़ाई होती हुई भी नज़र आई। बता दें कि इस घर से पहले ही नॉमिनेट हो चुकीं हरियाणा की सपना चौधरी को भी एक फिल्म ऑफर हुई है, जिसमें लीड रोल में अभय देओल के नाम की चर्चा है।

सांध्य दैनिक
क्राईम स्टोरी
website: www.crimestory.in
देहरादून
बुधवार, 10 जनवरी 2018

P

खुशखबरी! दिल्लीवासियों को मिलेगी 1000 बसों की सौगात

नयी दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 1,000 नयी स्टैंडर्ड फ्लोर बसें खरीदेगी। सिसोदिया ने कहा कि गैर वातानुकूलित बसें खरीदने का प्रस्ताव दिल्ली मंत्रिमंडल से मंजूर हो गया है और इन नयी बसों से बाहरी दिल्ली क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा, ''यह खरीद आठ महीने में शुरू होने की संभावना है और साल के आखिर तक सभी बसों के सड़कों पर आने की उम्मीद है।'' नयी बसों में 100 रेवला खानपुर डिपो, 250 द्वारका सेक्टर 22 डिपो, 120 खरखरी नाहर, 90 बवाना सेक्टर एक डिपो, 160 रानी खेड़स-। को और 140-140बसें रानी खेड़ा -। और रानी खेड़ा- ॥ को दी जाएंगी।

जार्जिया मे 20 टन वजनी ट्रक खींच देवभूमि के लाल

लांभाशू पहलवान ने रचा इतिहास

● राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश की तीनों सेनाओं के जर्नल से पा चुका है सम्मान ● राज्य स्तर पर कुश्ती मे जीते हैं 12 स्वर्ण पदक ● स्टूडेंट ओलम्पिक गेम्स के फाईनल मे पाकिस्तान के पहलवान को धूल चटाकर जीता था स्वर्ण पदक

अमित सूरी

ऋषिकेश। उम्र महज बीस वर्ष। योग्यता इण्टर पास । उपलब्धियां के पिटारे मेंराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित देश की तीनों सेना जर्नल से मिले सम्मान के अलावा राज्य स्तर पर 12 स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर सात मेडल।जी हां हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के लाल युवा लांभाशू पहलवानू की।देश के लिए ओलंपिक के कुश्ती इंवेंट मे स्वर्ण पदक जीत का सपना संजोने वाले युवा बाहुबली पहलवान लांभाशू यूरोप के जार्जिया मे बीस टन वजनी ट्रक को खींचकर इतिहास रचने की वजह से इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों मे हैं।इस अनोखे कारनामे के चलते उसका शुमार एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति के रूप मे हो गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल कर दिखाई।

कहते हैं पूत के पावं पालने मे ही पता चल जाते हैं ।इस कहावत को पूरी तरह से सच साबित कर दिखाया है तीर्थ नगरी के लाल लाभाशूं पहलवान ने ।आपको बता दे कि लांभाशू के पिता सुरेश पहलवान भी नामचीन पहलवान रहे हैं।लांभाशू को पहलवानी की विरासत घर से ही मिली।12 वर्ष से शुरू हुआ उसका पहलवानी का सफर कब जनून और फिर उसकी दुनिया बन गया उसे खुद पता नही चला।लांभाशू पिछले वर्ष एक बार फिर उस वक्त सुर्खियों मे आया जब श्री लंका मे आयोजित स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स के फाईनल मे उसने पाकिस्तान के पहलवान रिजवान को धूल चटाकर देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। उस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम भी श्रीलंका के दौरे पर थी। लांभाशू की उपलब्धि पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने लांभाशू से मिलकर उसकी पीठ थपथपाई थी।

दिल्ली मे 150 साल पुराने नोशेरा दंगल मे सबसे कम उम्र मे लगातार 9 कुश्तियां जीतकर खिताब हासिल कर चुके लांभाशू ने बताया कि उसका गोल ओलम्पिक मे स्वर्ण पदक जीतकर देशवासियों को उत्तराखंड की और से नायाब तौहफा देने का है जिसके लिए वह शिद्दत से अखाड़ों मे पसीना बहा रहा है।आने वाले वर्षो मे वह अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी कोशिश करेगा।

बौड़िगी गंगा फिल्म हुई सूपर हिट,बच्चे भी फिल्म देख खुशी से झूमें

ऋषिकेश। ऋषिकेश के रामा पैलेस थियेटर में प्रदर्शित हुई गड्वाली फीचर फिल्म बौड़िगी गंगा हुई सूपर हिटाउड़ान शिक्षण संस्थान के बच्चों ने भी पूरे उत्साह

के साथ देखी फिल्म।पहली बार थियेटर मे फिल्म देखने की खुशी बच्चों के चेहरों पर सहज ही देखी जा सकती थी।

बौड़िगी गंगा फिल्म ने वर्षो से एक अदद् हिट फिल्म के लिए तरस से गढवाल फिल्म उधोग को नई संजीवनी प्रदान करने का काम किया है।फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है फिल्म 5 वें दिन भी हाउसफुल रही। 5 वें दिन के दोपहर के शो को देखने सूबे के कबीना मंत्री सुबोध उनियाल भी हाल पहुँचे।इस मौके पर मंत्री उनियाल ने कहा कि अपनी बोली भाषा और संस्कृति के उत्थान हेतु हम सभी को आगे आने की जरूरत है सरकार ही और से जो भी सहयोग की आवश्यकता है उसके लिए प्रयास किया जाएगा।

लोकभाषा एवं लोकसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास किये जाने की बात कही। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता निर्देशक एवं सह निर्माता पुरुषोत्तम जेठूडी, अभिनेता प्रशांत गगोदिया,रणवीर चौहान, अभिनेत्री शिवानी भंडारी,गढवाल महासभा के अध्यक्ष डा राजे नेगी,अरुण प्रकाश बडोनी, विनीता बिष्ट, बीना जोशी, उत्तम असवाल, विनोद जुगरान, अशोक कुमार,नीतिन, मनोज राणा, लोक गायक धूम सिंह रावत, रवि कुकरेती आदि उपस्तिथ थे।

जंगली जानवरों के बाद घोड़ों ने भी किसानों का लूटा चौन,पेरों तले रौंद रहें है फसलें

ऋषिकेश। ग्रामीण क्षेत्र श्यामपुर न्याय पंचायत के किसान जँगली जानवरों के आतंक से जहाँ परेशान हैं वहीँ दूसरी ओर किसानों के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गयी है। ग्रामीण क्षेत्र श्यामपुर खदरी भल्ला फार्म के किसानों का चौन आवारा घोड़ों ने छीन लिया है। दर्जनभर से अधिक आवारा घोड़े किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय राज मार्ग पर दौड़ते ये आवारा घोड़े परेशानी का कारण बन रहे हैं।परेशान किसानों ने श्यामपुर चौकी प्रभारी संदीप कुमार को इस आशय की सूचना देते हुए प्रशासन से आवारा घोड़ों की रोकथाम के प्रबन्ध की गुहार लगायी है।सामाजिक कार्यकर्ता विनोद जुगलान का कहना है कि आवारा घोड़े न केवल फसल बर्बाद कर रहे हैं बल्कि इनके कारण राष्ट्रीय राज मार्ग पर यातायात भी बाधित हो रहा है कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है प्रशासन को चाहिए कि आवारा घूम रहे इन घोड़ों को कहीं जंगल में स्थानांतरित कर शीघ्र ही समस्या का निराकरण किया जाय। चौकी प्रभारी से मिलने गए किसानों में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद जुगलान,मण्डी समिति के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह रावत,श्यामपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य कोमल नेगी,महावीर प्रसाद उपाध्याय,देवेन्द्र सिंह रावत,कुलदीप असवाल,सुन्दर सिंह रावत,सुरेन्द्र रयाल आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

ग्रह कलेश के चलते पत्नी ने जहर पीकर किया आत्महत्या का प्रयास

ऋषिकेश अमित सूरी- ग्रह कलेश के चलते एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर किया आत्महत्या का असफल प्रयास ।महिला को बेहोशी की हालत में राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाण्ड गाव निवासी मीना40वर्ष पति ललित भट्ट के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई उसके बाद मीना अपने कमरे में गई और जहरीला पदार्थ लिया ।जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई ।उसकी हालत को बिगड़ता देख परिजन उसे गंभीर हालत में राजकीय चिकित्सालय ले आये जहाँ उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

यमकेश्वर के सुविख्यात गेंद मेला क्रिकेट चौम्पियनशिप मे दगड्या ने दिया स्वच्छता का संदेश

ऋषिकेश। त्योडों गाड गेंद मेला क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान दगड्या सामाजिक समिति के सभी खिलाडियों ने मैच समाप्ति के बाद त्योडों मैदान के चारों तरफचलाया सफाई अभियान। अभियान के तहत दगड्या के सदस्य खिलाडियों ने मैदान के चारों ओर से लगभग एक कुंतल कचरा एकत्रित कर खेल भावना का संदेश देते हुये अन्य टीमों को भी ये संदेश दिया कि खेल के बाद मैदान व उसके आस पास के एरिया को स्वच्छ रखा जाय ।ताकी वर्षा काल मे नदियों मे बाढ आने के कारण यह प्लास्टिक व कचरा गंगा नदी मे बहकर ना जाने पाये व गंगा नदी की स्वच्छता बरकरार रहे ।सामाजिक संस्था दगड्या के सुदेश भट्ट ष्दगड्याष्ने बताया कि आजकल पूरे यमकेस्वर मे हर तरफमैच हो रहे हैं ओर

मैच हार कर भी जीता दिल

मैच समाप्ति के बाद मैदान मे चारों ओर तरह तरह का कचरा नजर आता है जिससे पर्यावरण को खतरा पैदा होता है ।जो कचरा संभवतया खिलाडियों व दर्शकों के द्वारा छोड दिया जाता है ।दगड्या ने यमकेस्वर ही नही बल्कि समस्त प्रदेश मे चल रहे क्रिकेट आयोजनों मे सभी क्रिकेट टीमों से खेल के मैदानों की स्वच्छता को बरकरार रखने हेतु मैच के बाद सफाई का आह्वान किया है।अभियान मे संगठन के महासचिव अनुप ग्वाडी ,संगठन सचिव धीरेंद्र बिष्ट ,ज्योती पुष्पोला, शुभम नवानी ,अंकित उनियाल ,आशिष कंडवाल, अशोक प्रसाद ,दीपक कुमार, शुभम व सुदेश शर्मा ने बढ चढकर हिस्सा लिया ।

सम्पादकीय

तो क्या नकली बन रहे बीपीएल कार्ड

उत्तराखण्ड के अन्दर वर्षों से घोटाले व भ्रष्टाचारों पर नकेल लगाने के लिए लोकायुक्त की मांग की जा रही है और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूरी ने मजबूत लोकायुक्त का स्वरूप तैयार कर उसे राष्ट्रपति से भी स्वीकृत करा दिया था लेकिन लोकायुक्त के हंटर से डरने वाले राजनेताओं ने लोकायुक्त के गठन को लेकर नई पठकथा शुरू कर दी थी और कहा था कि वह अपने हिसाब से लोकायुक्त का गठन करेंगे। उत्तराखण्ड में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार ने भी सौ दिन में लोकायुक्त गठन करने का ऐलान किया था लेकिन सरकार अपने ही वायदे से आज मुकर गई और वह ऐलान कर रही है कि राज्य में न तो भ्रष्टाचार और न ही घोटाले हो रहे हैं इसलिए प्रदेश में लोकायुक्त का गठन नहीं किया जायेगा। सरकार के इन दावों को प्रकाश पांडे ने मरने से पहले आईना दिखा दिया और उसने सरकार की बेरूखी से तंग आकर जहर खाकर अपनी वीडियो में साफ संदेश दिया कि चार-पांच माह से वह मुख्यमंत्री के ओएसडी उर्वादत्त भट्ट से अपनी परेशानी को लेकर लगातार बात कर रहा था। प्रकाश पांडे ने अपने वीडियो में कहा कि जब आखिरी बार उसने उर्वादत्त भट्ट से बात की तो उर्वादत्त भट्ट ने उससे यह कहा कि अगर वह कहीं से बीपीएल कार्ड बनवाकर ले आयेगा तो वह उसकी चालीस-पचास हजार रूपये की मद्द करा देगा। उर्वादत्त भट्ट के इस कथन पर प्रकाश पांडे का कहना था कि वह टैक्सपैड है और उर्वादत्त भट्ट को ज्ञान ही नहीं है। आज प्रकाश पांडे सरकारी सिस्टम की बेरूखी के चलते भले ही हमेशा के लिए अपने परिवार को अकेला छोडकर मौत की नींद सो गया हो लेकिन बहस इस बात की छिड गई है कि मुख्यमंत्री का एक ओएसडी अगर किसी को फर्जी बीपीएल कार्ड बनवाकर लाने का ज्ञान दे रहा है तो उसको लेकर यही सवाल खडे हो रहे हैं कि क्या राज्य के अन्दर बीपीएल कार्ड भी फर्जी तरीके से बनाने का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी को इतना गम्भीर होना चाहिए कि उसका कोई भी कथन सरकार का कथन होता है लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कर्ज के बोझ के तले दबे एक ट्रांसपोर्टर को जिस तरह से सरकारी मद्द दिलाने के लिए फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर लाने का फंडा समझाया उससे सरकार पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गये हैं और इस बात को लेकर भी बहस छिड गई है कि सरकार के अंग भी लोगों को फर्जी काम करने के लिए सलाह दे रहे हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डबल इंजन की सरकार के राज में क्या चल रहा है। अगर ओएसडी गम्भीरता पूर्वक प्रकाश पांडे की बात को सुनकर उसे सरकार के मुखिया के सामने रखते तो हो सकता था कि उसका कोई हल निकल जाता लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा एक कर्जदार को महीनों मद्द दिलाने का झुनझुना पकडवाने का जो हथकंडा अपनाया गया उससे उत्तराखण्ड से लेकर दिल्ली तक में डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खडा किया जा रहा है और कांग्रेस ने भी सरकार की बेरूखी को लेकर डबल इंजन सरकार पर जमकर हल्ला बोलना शुरू कर रखा है और यह सारा मामला उस समय घटित हुआ जब राज्य में कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने हैं ऐसे में प्रकाश पांडे की मौत पर हो रही राजनीति से सरकार के माथे पर जरूर बल पड रहे होंगे लेकिन सरकार के सामने यह भी सवाल खडा हो गया है कि अगर कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति कर्ज के बोझ में दबकर सरकार से मद्द चाहता है तो क्या उसे तब तक मद्द नहीं मिलेगी जब तक उस पर बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति होने का ठप्पा नहीं लग जायेगा। मुख्यमंत्री के ओएसडी का प्रकाश पांडे को फर्जी बीपीएल कार्ड बनाने का सुझाव देना राज्य में एक नई बहस को जन्म दे गया है कि क्या सरकार भी ऐसी होती है जो एक मजबूर को सलाह दे रही है कि अगर उसे मद्द चाहिए तो वह फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर उसके सामने आये।

आतंकवाद का किसी भी धर्म में कोई आधार नहीं है: उपराष्ट्रपति

नयी दिल्ली। एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि आतंकवाद का दुनिया के किसी भी धर्म में कोई आधार नहीं है और उन्होंने सभी देशों से इस बुराई से निबटने के लिए ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। नायडू ने यहां पहले पीआईओ संसदीय सम्मेलन के समापन संबोधन में कहा, 'दुर्भाग्य से कुछ लोग आतंकवाद पर धर्म की चादर डाल रहे हैं लेकिन आतंकवाद का दुनिया के किसी भी धर्म में कोई आधार नहीं है और लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि आतंकवाद की विध्वंसकारी ताकतों से लड़ना अनिवार्य है क्योंकि वह विकास की राह में रोड़ा अटका रहा है तथा सभी देशों को इसे मानवता के लिए खतरा मानकर उस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिये बगैर नायडू ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का साथ देने और उसका वित्तपोषण करने में यकीन करते हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनिर्धारित पाकिस्तान यात्रा का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पीआईओ संसदीय सम्मेलन ने प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को विविधता प्रदान की है और इससे पीआईओ निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद, आवागमन एवं विचारों के आदान-प्रदान के नये मंच खुलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'वैसे हम भिन्न भिन्न धर्मों का मानते हैं, हमारे पासपोर्ट के रंग अलग अलग हैं, हमारे पूर्वज भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए और हमारी मातृभाषाएं एवं प्रथाएं भी अलग अलग हैं लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।'

बाड़मेर में मोदी की रैली के लिए नमक के खदानों को किया जा रहा है बंद: अली अनवर

नयी दिल्ली। राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रधानमंत्री की 16 जनवरी की प्रस्तावित यात्रा के आयोजन के लिए कई नमक खदानों को बंद कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं के समक्ष कुछ प्रभावित ग्रामीणों को भी पेश करते हुए दावा किया कि रिफाइनरी का रास्ता साफ करने के लिए 200 से ज्यादा नमक खदान बंद किए जाएंगे। इस रिफाइनरी की आधारशिला मोदी उस दिन रखेंगे। पूर्व जदयू सांसद का दावा है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसी परियोजना के लिए चार साल पहले ही आधारशिला रखी थी और यहां दो लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वजह से मोदी दोबारा ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, "अगर ये खदान बंद होते हैं तो सैकड़ों गांव वाले अपनी आजीविका खो देंगे। सरकार को इन लोगों का पुनर्वास कराना चाहिए। और अच्छा होगा कि इन खदानों को बंद न किया जाए।" अलवर और राजस्थान लोकसभा सीटों पर 29 जनवरी को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों के परिणाम एक फरवरी को घोषित होंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र : कुशलता की दरकार

वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. वर्ष के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 घोषित की. राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएमसी) बिल लाया जो संसद में पारित होने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), अधिनियम, 1956 का स्थान लेगा. मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 व एचआईवी एंड एड्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट पारित किया गया. हृदय रोग संबंधी स्टेंट्स तथा विकलांगों के अंग प्रत्यारोपण संबंधी लागतों को विनियमनों के जरिए माकूल बनाया गया. डॉक्टरों से कहा गया कि नुस्खों में दवाओं के जेनरिक नाम लिखें. नीति आयोग ने तीन वर्षीय कार्ययोजना (जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल है) जारी की; राज्य स्तर पर देश में पहली दफा हृदय रोग संबंधी आंकड़े जारी हुए तथा नेशनल न्यूट्रीशन मिशन की घोषणा हुई. वर्ष के उत्तरार्ध में तमाम खबरें थीं, जिनमें समूचे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब गुणवत्ता का जिक्र था. ये खबरें सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों द्वारा मुहैया कराई जारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर थीं. गोरखपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा देश के कुछ हिस्सों में जिला अस्पतालों में बच्चों की मृत्यु होने की खबरें मिलीं. दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने तो हद ही कर दी जब उसने एक जीवित शिशु को मृत घोषित कर दिया. खबरें ऐसी भी थीं कि कुछ अस्पताल मरीजों से बेतहाशा वसूली कर रहे थे. बीता साल केंद्रीय बजट 2016-17 में घोषित नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को आरंभ किए जाने की प्रतीक्षा में ही गुजर गया. इस महत्त्वाकांक्षी घोषणा में मंसूबा जताया गया था कि 150,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों (एचडब्ल्यूसी) में तब्दील किया जाएगा. घोषणा की गई थी कि साल 2017 में कुल स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से 4,000 (या कुल उपकेंद्रों के 3त्न) एचडब्ल्यूसी में बदल दिए जाएंगे. कह सकते हैं कि 2017 का साल ऐसा था जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तमाम नीतियों और नियम-कायदों की बात थी. एनएसपी, 2017 का लक्ष्य है कि 'सभी तक बिना वित्तीय अड़चन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाएं पहुंचाई जाएं'. यह मंसूबा सही मायनों में 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) संबंधी वैश्विक चर्चा को ही बयां करने वाला है. पंद्रह वर्ष पूर्व घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में कुछ लक्ष्य प्रस्तावित थे; लेकिन जब एनएचपी, 2017 जारी की गई तो अनेक लोगों को लगा कि कुछेक लक्ष्यों को छोड़कर एनएचपी, 2002 को ही दोहरा दिया गया है. कमोबेश कहा जा सकता है कि बीते 15 से 20 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है. दरअसल, नीति-नियमन अपने तई कोई समाधान नहीं होते. स्पष्ट है कि भारत में स्वास्थ्य पण्राली को दुरुस्त करना है, तो पूर्व में किए जा चुके प्रयासों से सिरे से भिन्न उपाय करने होंगे. जून, 2014 में दिए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन में समाधान तलाशा जा सकता है. मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, 'जरूरी है कि हम व्यापकता में सोचें. कुशलता, स्तर और त्वरिता को ध्यान में रखकर विचार करेंगे तो भारत के तेजी से आगे बढ़ने के रास्ते उतने ही आसान होंगे.' हालांकि उनकी टिप्पणी किसी अन्य संदर्भ में थी, लेकिन यह स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी लागू होती है. आर्थिक वृद्धि को सर्वोच्च रखते हुए अधिकांश एलएमआईसी चाहते हैं कि भारत समेत सभी देशों के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर रहे. इसलिए स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक विमर्श अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाना जरूरी है. किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए स्वस्थ नागरिक होना अत्यावश्यक शर्त है. संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास संबंधी उच्चस्तरीय आयोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तथा लांचट की रिपोटरे के मुताबिक, जीवन प्रत्याशा में एक अतिरिक्त वर्ष की बढ़ोतरी से जीडीपी में 4त्न का इजाफा हो जाता है. और स्वास्थ्य पर व्यय किया गया प्रत्येक डॉलर 9 गुणा निवेश के रूप में मिलता है. स्वास्थ्य संबंदी व्यय लोगों को गरीबी और वंचना के दलदल में धकेलने के बड़े कारक होते हैं.

टोक्यो घोषणा, दिसम्बर, 2017 से यूएचसी को वैश्विक स्तर पर गति मिली है. यूएचसी के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत एनएचपी का हिस्सा हैं. देश में अनेक सकारात्मक बदलावा आए हैं, और आजादी के सत्तर वर्ष पश्चात यह एक अवसर है जब नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कायाकल्प कर देने वाले उपाय अपनाए जा सकते हैं. भारत में यूएचसी को क्रियान्वित किया जाना भले ही चुनौतीपूर्ण हो लेकिन यह ऐसा लक्ष्य तो नहीं ही है, जिसे हासिल न किया जा सकता हो. कुछ 'बड़ा सोचने' से यह भी आशय यह भी है कि भारत को यूएचसी को आगे बढ़ाने में बढ़कर भूमिका निभानी चाहिए. बेहतर स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने तथा भारत में यूएचसी को लागू करने के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के मौजूदा कार्यबल को नये सिरे से दक्ष बनाया जाए. दक्ष मानव संसाधन की उत्पादकता में इजाफा किया जाए. इस क्षेत्र में रोजगार सृजन और दक्ष स्वास्थ्य कार्यबल होने से आर्थिक विकास को संबल मिलेगा. 'कुशल भारत' पहल को भी मजबूती मिलेगी. भूखा होने पर छोटे निवाले से काम नहीं चलता, 'बड़े निवाले' की जरूरत होती है. कई दफा स्वास्थ्य पण्राली में नतीजे हासिल करने के लिए हदों को पार करने की जरूरत महसूस होती है. इतना ही नहीं आगामी 12 वर्षों के लिए लक्ष्य तय कर लेने होंगे. कम-से-कम दो-तीन राज्य तो सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जता ही सकते हैं कि वे आगामी 3 से 5 वर्ष के भीतर यूएचसी को हासिल कर लेंगे. कुछ राज्यों को एनएचपी, 2017 के प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने बजट का 8त्न इस्तेमाल करने में सफल होना चाहिए. ऐसा खाका तैयार किया जाए ताकि आगामी 6-7 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जीडीपी का 3-4त्न व्यय किया जाना सुनिश्चित हो सके. दशकों से भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र योजना बनाने पर तो ध्यान देता रहा है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन के स्तर पर बहुत कम किया जा सका है. योजना आयोग को भंग किया जा चुका है लेकिन पहले जैसा ढर्रा अभी भी बना हुआ है.

सामयिक : नया साल नई इबारतें

नया साल नई इबारतें लेकर आया है. 21वीं सदी की पहली पीढ़ी बालिग हो रही है, और क्षितिज पर संभावनाओं और चुनौतियों के बादल घुमड़ रहे हैं. नई वयस्क पीढ़ी को शिक्षा खासकर उच्च शिक्षा, रोजगार और कॅरियर चयन की उलझनों से तो मुकाबिल होना ही है, बेहद उलझे राजनैतिक विकल्पों का चयन भी उसकी बाट जोह रहा है. आखिर, उसके वोट देने की उम्र हासिल करने का साल 2018 ऐसा विरला होगा जब शुरुआत से अंत तक चुनावों की गहमागहमी ही जारी रहेगी. इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते वर्ष 2017 के आखिरी दिन अपने वप्रात में मन की बात में उनसे वोट की बात की और उम्मीद जताई कि वह राजनीति को नई दिशा देगी. अभी दहलीज पर पांव रख रही पीढ़ी से यह उम्मीद कुछ नाइंसाफी-सी लगती है. लेकिन कोई करे भी क्या? इस साल चुनावी राजनीति किसी और चीज के लिए फुर्सत देती नहीं लगती है, खासकर ऐसे माहौल में जब दांव सबसे ऊंचे लगे हों. आखिर, आठ राज्यों-मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक (साल के शुरू में) और मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान (साल की आखिरी तिमाही में)-के चुनाव होते ही अगले साल यानी 2019 में आम चुनावों की वेला आ जाएगी. फिर बीता वर्ष जाते-जाते राजनीति, अर्थव्यवस्था यानी सभी को ऐसा गड्डमड्ड कर गया है कि संभावनाओं और आशंकाओं के बीच बेहद महीन फर्क ही रह गया है.

राजनीतिक मोर्चे पर गुजरात चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुआई में भाजपा जीत तो गई लेकिन खुशी खिली विपक्ष में. विपक्ष खासकर कांग्रेस में तो हारकर भी ऐसा उत्साह लौट आया कि उसमें आक्रामकता लौट आई है. दरअसल, कांग्रेस से भी बढ़कर गुजरात में युवा नेताओं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी ने भाजपा और मोदी की अपराजेय-सी छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए और उनके विकास के गुजरात मॉडल को संदिग्ध बना दिया. फिर, नोटबंदी और जीएसटी के नतीजों ने भी सरकार हाथ खाली कर दिए. वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े 6.5 फीसदी आए और सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि जीएसटी नोटबंदी से प्रभावित नहीं हुई लेकिन भाजपा के ही राज्य सभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह खुलासा करके उसे बेमजा कर दिया कि ये आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पर दबाव डालकर हासिल किए गए हैं. इसी तरह अभी जीएसटी की पेचीदगी की वजह से राजस्व उगाही में भारी कमी के आंकड़े भी आ गए हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका है यानी सरकार चाह कर भी इस साल अपने आखिरी पूर्ण बजट में बहुत कुछ लुभावने प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती. एक अटकल यह भी लगाई जा रही है कि सरकार इस कमी की भरपाई के लिए विश्व बैंक से 50 अरब डॉलर का कर्ज लेने की सोच रही है. जाहिर है, लगभग दो-ढाई दशक बाद देश के सामने ऐसे हालात मौजूद होंगे. मामला सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था का ही नहीं है, समाज भी कई तरह के सवालों से रू-ब-रू है. युवा, महिला, किसान, छोटे व्यापारी हर ओर एक बेचैनी-सी दिखाई पड़ रही है. इसे चुनावी जीत-हार से अब शायद ही ढंका जा सके. बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि रोजगारविहिन आर्थिक वृद्धि के आंकड़े अब लुभाते नहीं हैं. अर्थव्यवस्था के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग में सुधार आस्ति जगाने के बदले गहरे सवाल पैदा कर रही है. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ही कहा है कि ये आंकड़े तो पैसे देकर हासिल किए जा सकते हैं. लेकिन इससे भी बढ़कर समाज में हो रही हलचलें हैं. गुजरात में सबसे तीखा विभाजन, चुनावी नतीजों के संदर्भ में, गांव और शहर के बीच दिखा. इससे विकास के ढें पर गहरे सवाल खड़े हुए हैं. गुजरात ही क्यों, पूरे देश में दलित और पिछड़ी जातियां ही नहीं, अब तक ताकतवर और संपन्न मानी जाने वाली जातियां भी संकट महसूस कर रही हैं. अलग-अलग हिस्सों में जाट, कापू, मराठा, गुर्जर अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं. यही नहीं, सवर्ण जातियों की ओर से भी आरक्षण की मांग उठ रही है. यह उस संकट की ओर इशारा है, जो नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों से निकले विकास के तौर-तरीकों से पैदा हुए हैं. किसान, मजदूर, समाज के पुराने ताकतवर तबके, छोटे व्यापारी सब खस्ताहाल हैं. मगर बड़े उद्योगपतियों की संपत्तियों में लगातार इजाफा हो रहा है. बेशक, इस सदी के शुरू में मध्य वर्ग को कुछ नौकरियां मिलीं. नये हुनर के लिए शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण भी हुआ और देश में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों की बाढ़ आ गई लेकिन अब सुनहरा सपना टूट रहा है. नौकरियां भी सिमटीं और थोक भाव में ऐसे निजी संस्थानों के बंद होने की खबरें भी आने लगीं. ऐसे माहौल में 18 वर्ष में प्रवेश कर बालिग हो रही 21वीं सदी की पहली पीढ़ी के सामने हकीकत की नई परतें खुलती दिख रही हैं. पिछली सदी के आखिरी दशक में पैदा हुई पीढ़ी भी ऐसी ही हकीकत से 2010-11 में हुई थी, जिसके नजारे अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान दिखे थे. उससे राजनीति की फिजा एकबारगी बदल गई थी. मगर उससे विकास की धारा नहीं बदली, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण के जरिए एक नई फिजा तैयार हुई, जिसमें अन्ना आंदोलन के दौरान समाज को पारदर्शी बनाने के मुद्दे ही नेपथ्य में चले गए. अब लोकपाल, याराना पूंजीवाद जैसे मुद्दों पर अब बात भी नहीं होती लेकिन उसके दंश डूबत कर्ज से लेकर कई मामलों में दिखते हैं. याद करें 21वीं सदी को भारत की तस्वीर बदलने के सपने के रूप में पेश किया जाता रहा है. लेकिन यह सदी तो और चुनौतियां लेकर आ रही है. लेकिन ऐसे ही चुनौतीपूर्ण महौल में उम्मीद की कोपलें भी फूटती हैं. दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास भी कोई वैकल्पिक नजरिया नहीं है. इसलिए यह कहने में कोई अति-उक्ति जैसी बात नहीं होगी कि नई पीढ़ी को अपने सभी विकल्पों पर खूब सोचना-विचारना पड़ सकता है.

वन विभाग को मिली सफलता, जाल में कैद किया गुलदार

नगर संवाददाता

देहरादून। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में गुलदार का खौफ लंबे समय से बना हुआ था और कई क्षेत्रों में गुलदार के आतंक से लोग भयभीत थे और आज सुबह भी सुमनपुरी स्थित बैंक कालोनी में एक युवक को घायल किया और बाद में युवक को प्राथमिक उपचार के छुटटी दे दी गई। इस घटना से वन विभाग की टीम हरकत में आई और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार गुलदार को जाल बिछाकर कैद लिया गया।

यहां सुमनपुरी स्थित बैंक कालोनी में सुबह बाथरूम गए एक युवक को गुलदार ने पंजा मारकर घायल कर दिया। बताया गया कि गुलदार पहले से ही बाथरूम में छिपा बैठा था। घायल युवक का दूंन अस्पताल में उपचार कराया गया और बाद में प्राथमिक उपचार के बाद छुटटी दे दी गई।

इस घटना के बाद घायल करने के बाद गुलदार डील की तरफ भागा और इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले पांच दिन से अधोईवाला, बैंक कॉलोनी एवं आसपास की कॉलोनी में गुलदार को देखा गया था और वन विभाग को भी सूचना दी गई। आज सुबह की घटना के बाद वन विभाग की टीम बैंक कालोनी में तैनात हो गई और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार गुलदार को जाल बिछाकर कैद कर लिया गया और क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली।

प्रकाश पांडे के परिजनों को एक करोड़ मुआवजा दे सरकार

नगर संवाददाता

देहरादून। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश बहुगुणा ने ट्रांसपोर्टर प्रकाश पाँडे की असामयिक मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख व्यक्त करते हुये इसके लिये पूरी तरह से भाजपा सरकार की व्यापार विरोधी आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है।

यहां पार्टी के फालतू लाईन स्थित कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश बहुगुणा ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा है कि कल एक और जिंदगी नोटबंदी व जीएसटी के गलत फैसलों के दुष्परिणामों की भेंट चढ़ गई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी व जीएसटी के बाद से ही देश का छोटा व मध्यम व्यापारी वर्ग आर्थिक दबाव में जी रहा है। केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार व अर्थव्यवस्था बरबादी के कगार पर पहुँच चुकी है।

इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी कुलदीप सहदेव ने इस घटना को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुये प्रदेश के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत को निशाने पर लेते हुये कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फमनमानी कर रहे हैं और उनके राज में न तो जनभावनाओं का सम्मान है और न ही जनसंवेदनाओं से उन्हें कोई सरोकार है। उनका कहना है कि केन्द्र की मोदी सरकार की तरह प्रदेश की त्रिवेन्द्र रावत सरकार भी तानाशाही का रवैया अपना रही है और राज्य में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है।

उनका कहना है कि चुनाव से पूर्व भाजपा ने घोषणा की थी की उत्तराखंड में उनकी सरकार बनते ही किसानों के ऋण माफकर दिए जायेंगे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जिस प्रकार केन्द्र सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुए प्रकाश पाँडे ने प्रदेश सरकार के रवैये से निराश होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह आत्महत्या का नहीं बल्कि सीधा हत्या का मामला है और इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री समय रहते प्रकाश पाँडे की आपबीती सुन-समझ लेते तो यह दुखद घटना नहीं घटती। प्रदेश सराकार से मांग करती है कि स्वर्गीय पाण्डे के परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी सेवा में लिया जाए और परिवार को राजकीय कोष से न्यूनतम एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस अवसर पर प्रेसवार्ता में देहरादून जिलाध्यक्षा उमा सिसौदिया, देहरादून महानगर अध्यक्ष विशाल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष विनोद बजाज व सुदेश चौरसिया आदि उपस्थित थे।

नशे के माफ्याओं पर अंकुश लगाये प्रदेश सरकार

नगर संवाददाता

देहरादून। युवा सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश पांडे ने राज्य के विभिन्न यूएस कॉल सेंटरों में काम करने वाले युवाओं को नशीले पदार्थों का सेवन कराने वाले व बेचने वाले नशे के माफ्याओं पर अंकुश लगाये जाने की मांग प्रदेश सरकार से की है।

यहां परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि दून व राज्य के कॉल सेंटर के नाम पर राज्य की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है दून में जितने कॉल सेंटर चल रहे है किसी के पास रजिस्ट्रेशन तक नहीं है और यहां बाहरी लोगों द्वारा डीओटी के लाईसेंस के बिना संचालन किया जा रहा है यह बाहरी लोग यूएसए व अन्य देशों के लेपटॉप हैग कर उस पर विन्डो वायरस डालते है जिससे उक्त व्यक्ति का लैपटॉप, डेक्सटॉप, मोबाइल हैग हो जाता जिसमें उसकी सारी प्राईवेसी हैग कर उसका गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है और सर्विस के नाम पर लोगों को डरा धमका करके रूपयों की मांग की जाती है और कई बार उक्त गिरोह के लोगों के माध्म से कई लोगों को ठगा भी जा चुका है।

उनका कहना है कि इसमें जितने भी टूल्स प्रयोग किये जाते है वह हैगिंग टूल्स है तथा यह भी सामने आया है कि ऐसे मामलों की कई शिकायतें दर्ज की गई है लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि पुलिस को तत्काल इस मामले में कार्यवाही की जानी चाहिए। उनका कहना है कि युवा सेना ऐसे कॉल सेंटरों को चिन्हित कराते हुए तालाबंदी करने को मजबूर होगी। इस अवसर पर युवा सेना के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

सेना स्थानीय लोगों के साथ मनाएगी सेना दिवस

अल्मोड़ा। हमेशा लोगों से दूरी बनाकर रखने वाली सेना ने अब जनता को अपने कार्यकर्मो और उनके साथ मिलकर समारोह का आयोजन करने की तैयारियां शुरू कर दी है। सेना ने इस बार सेना दिवस का आयोजन आत्मविश्वास और विनीतभाव क साथ अल्मोड़ा कैंट में करने की योजना बनाई है। 12 जनवरी को अल्मोड़ा कैंट में सेना ने एक शानदार और मैत्रीपूर्ण छवि प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निवासियों के लिए आर्मी बैंड डिस्प्ले का आयोजन गरुड़ डिवीजन की तरफसे किया जाएगा। यह समारोह आर्मी दिवस की स्मृति में राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा होगा। सेना यूनिट का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निवासी जिसमें खासतौर से युवावर्ग तक अपनी पहुँच बनाना और उनको सेना में अधिक से अधिक तादाद में आने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस समारोह का आयोजन सेना और स्थानीय प्रशासन के संबंधों को प्रोत्साहन देना है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा जिसमें सेना के बारे में लोगों को जानने और सेना के जवानों के साथ खुशी बाँटने का अवसर मिलेगा।

18वीं प्राचीन श्री जगन्नाथ रथयात्रा का आयोजन 14 को

देहरादून। राजधानी में 18वीं प्राचीन श्री जगन्नाथ रथयात्रा का आयोजन 14 जनवरी को परेड ग्राउंड से किया जायेगा और रथयात्रा का समापन महोत्सव 2० जनवरी को किया जायेगा।

यहां परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होते होते हुए ट्रस्टी व श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के सदस्य अजय गोयल ने कहा है कि राजधानी में 18वीं प्राचीन श्री जगन्नाथ रथयात्रा का आयोजन 14 जनवरी को परेड ग्राउंड से किया जायेगा और रथयात्रा का समापन महोत्सव 2० जनवरी को किया जायेगा। उनका कहना है कि रथयात्रा प्रात: दस बजे आरंभ होगी।

उनका कहना है कि इससे पूर्व श्री जगन्नाथ मंदिर विष्णु विहार में प्रात: आठ बजे से भव्य दर्शन महा आरती की जायेगी और प्रात: साढे आठ बजे से श्री ठाकुर विग्रहों का प्रस्थान किया जायेगा और सांय छह बजे नगर भ्रमण के पश्चात भव्य आरती की जायेगी। उनका कहना है कि यह रथयात्रा परेड ग्राउंड से आरंभ होकर कनक चौक, एस्ले हॉल चौक, गांधी पार्क, घंटाघर, पल्टन बाजार, दर्शनी गेट, गांधी रोड, अग्रसैन चौक, हरिद्वार रोड होते हुए कुष्णा वैडिंग प्वाइंट में पहुंचकर विश्राम लेगी और वहां पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर समिति के अनेक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।

उपनल कर्मचारियों के समर्थन में यूकेडी का प्रदर्शन

नगर संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलित उपनल कर्मचारियों की समान वेतन समान कार्य ,सुरक्षित भविष्य तथा वर्तमान में मृत पदों पर कार्यरत पदों को पुनर्जीवित करने तथा और असृजित पदों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के पदों को सृजित करने संबंधित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के जरिये मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांगों को तत्काल हल करने का आग्रह किया।

यहां दल के कार्यकर्ता संरक्षक बी डी रतूडी एवं महानगर अध्यक्ष संजय क्षेत्री के नेतृत्व में दल के कार्यालय में इकटठा हुए और वहां से प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उपनल कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा तथा समान कार्य, समान वेतन की मांग को लेकर कई वर्षों से आंदोलनरत है। उनका कहना है कि किंतु राष्ट्रीय दलों द्वारा केवल विपक्ष में रहने के दौरान उपनल कर्मचारियों को गुमराह कर के उनके वोटों का दोहन मात्र किया जाता है और सत्ता पाते ही राष्ट्रीय दलों के नेता उपनल कर्मचारियों के सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष में बैठने के दौरान राष्ट्रीय दलों के नेता सत्तापक्ष पर उपनल कर्मचारियों के बहाने उपनल कर्मचारियों के मंच पर दहाड़ते नजर आते हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल का साफमानना है कि उपनल कर्मचारी कम वेतन पर भी काम कर के पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में सहायक साबित हुए हैं। लेकिन सरकार द्वारा लगातार पलायन रोकने के झूठे दावे किए जाने के बावजूद उपनल कर्मचारियों को पारितोषिक देने के बजाय उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका कहना है कि लगभग 6००० से 8००० रूपये प्रतिमाह पर वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे गरीब कर्मचारियों के ऊपर हमेशा अचानक सेवाएं समाप्त किए जाने का खतरा मंडराता रहता है। जहां राजकीय कर्मचारियों से आठ घंटे काम लिया जाता है वही प्रदेश के राजकीय विभागों, सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों, जल संस्थान, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण तथा केंद्र पोषित परियोजनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे उपनल कर्मचारियों से 12 घंटे तक कार्य लिया जाता है। इन कर्मचारियों से भविष्य हेतु सरकार द्वारा कोई नियमावली नहीं बनाई गई है तथा इनकी तनख्वाह का यह आलम है कि कहीं एक वर्ष तो कहीं दो वर्ष तक इनको तनख्वाह नहीं मिल पाती है।

उनका कहना है कि ऐसे में यह बहुत विचारणीय प्रश्न है कि उपनल कर्मचारी अपने बच्चों के स्कूल की फीस, मकान का किराया, दूध का बिल इत्यादि किस तरह भुगतान करता होगा। उनका कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने तथा पलायन को रोकने के अपने फैसले पर अटल रहते हुए प्रदेश सरकार को यह चेतावनी देता है कि राज्य में उपनल कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे 24 हजार युवाओं के रोजगार पर यदि शीघ्र उचित फैसला नहीं लिया गया तो उत्तराखंड क्रांति दल पूरी ताकत के साथ उपनल कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेगा। उनका कहना है कि सरकार ने शीघ्र ही उपनल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो सड़कों पर उतरकर जनांदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर दल के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

प्रदेश सरकार के खिलाफ क्रमिक अनशन

नगर संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मंच ने अपनी सात सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए अपने आंदोलन को जारी रखते हुए प्रदेश सरकार को के खिलाफ प्रदर्शन कर धरना दिया वहीं आंदोलनकारी क्रमिक अनशन पर बैठे रहे और कहा कि अब सरकार के खिलाफ आर पार का आदोलन चलाया जायेगा। इसके लिए रणनीति तैयार की जायेगी। उनका कहना है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जो चिंता का विषय है।

यहां मंच से जुडे हुए आंदोलनकारी कचहरी स्थित शहीद स्थल में अध्यक्ष नंदाबल्लभ पांडेय के नेतृत्व में इकटठा हुए और वहां पर उन्होंने अपनी सात सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और अपने क्रमिक अनशन को जारी रखा। इस अवसर पर क्रमिक अनशन में राजेश्वरी भटट, उर्मिला जोशी, ऊषा रावत, मीता रावत, बिल्लू नेगी, सरोज उप्रेती, सीमा नेगी, रतना रावत, विक्रमा देवी बिष्ट, निशा सेमवाल, गीतांजली पांडे, सरिता सकलानी, पवित्रा राणा, अंजू मिश्रा, ऊषा देवी सहित अनेक आंदोलनकारी बैठे। वक्ताओं ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के हितों के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दे रही है जिसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।

उनका कहना है कि वहीं वह सरकार की जन विरोधी नीतियों से नाराज दिखाई दे रहे है। उनका कहना है कि अभी तक 1० प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण नहीं मिल पाया है जो चिंता का विषय है। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा आंदोलनकारियों को शीघ्र ही प्रदान किया जाना चाहिए और सेनानियों

के आश्रितों को रोजगार में समायोजित किये जाने तथा समीवर्ती जिलों से पलायन पर पूर्ण रूप से रोक लगाये जाने और आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को शीघ्र ही प्रदान किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि समूचे उत्तराखंड को आरक्षित किया जाये और मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे के दोषियों को फांसी दिये जाने की मांग की गई है लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी प्रकार की कोई नीति तैयार नहीं की गई है। उनका कहना है कि आज आंदोलन को काफी दिन हो गये, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है जो चिंता का विषय है। उनका कहना है कि लगातार आंदोलनकारियों के हितों के लिए संघर्ष किया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार इस ओर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। इस अवसर पर अनेक आंदोलनकारी मौजूद थे।

ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की मौत पर कांग्रेस ने दहन किया सरकार का पुतला

नगर संवाददाता

देहरादून। ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे की मौत पर आक्रोशित कांग्रेसजनों ने जुलूस निकालकर केन्द्र व प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और कहा है कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं दिखाई दी और स्वर्गीय पांडे को उचित उपचार नहीं दिया गया।

यहां कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में इकटठा हुए और वहां से प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एस्ले हॉल चौक पहुंचे जहां पर केन्द्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस अवसर पर प्रीतम सिंह ने हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उत्तराखण्ड के

इतिहास का काला दिन है। उनका कहना है कि सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं रही है। उनका कहना है कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी मजिस्ट्रेट से जांच कराने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेवार है। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों जिसमें नोटबन्दी एवं जीएसटी जैसे तुगलकी फैसले जनता पर थोपने से व्यवसाय से जुड़े लोग तबाही की कगार में पहुंच गये है और भुखमरी तक पहुंच गए है । उनका कहना है कि प्रकाश पांडे मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए थे और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी इसलिये परेशान होकर उन्होंने सल्फास खा लिया।

उनका कहना है कि इस सारे प्रकरण के बाद भी राज्य सरकार नहीं चेती और अच्छा होता दिल्ली में अखिल भारतीय आयर्वेदिक संस्थान भेजते तो जान बच जाती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनका कहना है कि सरकार के नकारे पन और जनविरोधी निर्णयों को लेकर कांग्रेस व्यापक स्तर पर जनांदोलन करेगी और आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के पुतले फूंके गये। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, जोत सिंह बिष्ट, गरिमा दसौनी, लालचन्द शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार, प्रभुलाल बहुगुणा, राजेन्द्र शाह, पृथ्वीराज चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।

अज्ञात चोरों ने किया कार पर हाथ साफपुलिस ने शुरू की जांच

ऋषिकेश। चोरों ने किया कार पर हाथ साफघर के बाहर से ही कार चुराकर हो गये फरार। जाड़े की सर्द रातों मे वाहन चोर तीर्थ नगरी मे एक बार फिर से सक्रिय हो गये हैंऐसे ही एक मामले मे बीती रात अज्ञात चोर मनिराम मार्ग निवासी इन्द्रजीत सिंह की इंडिका कार पी बी 1०- 4००6 पर हाथ साफ करने मे कामयाब हो गये।मामले का पता आज सुबह उस वक्त चला जब बाहर आकर इन्द्रजीत के परिवार वालों ने गलि किनारे खड़ी कार को गायब पाया। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मोका मुआयना कर तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

सांध्य दैनिक
क्राईम स्टोरी
website: www.crimestory.in
देहरादून
बुधवार, 10 जनवरी 2018

प्रकाश पांडे की मौत से डरी सरकार!

● ट्रांसपोर्टर पांडेय के परिजनों को सरकारी मद्द

● मद्द के बाद हुआ अंतिम संस्कार, हल्द्वानी में बाजार बंद

नैनीताल। नोटबंदी और जीएसटी से परेशान, सरकार में सुनवाई न होने की वजह से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचने वाले ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे का के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था लेकिन सरकार के मुखिया ने जब परिजनों को मुआवजा व परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात कही तो परिवार के लोग प्रकाश पांडे का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुये। वहीं प्रकाश पांडे की मौत से नाराज व्यापर मंडल ने हल्द्वानी बाजार बंद रखा और कांग्रेसी नेताओं ने जलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जीएसटी के दिख रहे प्रभाव को लेकर पुतला भी फूंका गया।

बता दें कि प्रकाश पांडे का पार्थिव शरीर रात करीब ढाई बजे काठगोदाम स्थित आवास पर पहुंचा। पुलिस फोर्स की पर्याप्त मौजूदगी के बीच शव घर पर पहुचते ही पत्नी कमला पांडे, मां देवकी देवी और बच्चे मोहित और भूमि प्रकाश के बेजान हो चुके शरीर से लिपटकर बार-बार उन्हें बुलाने लगे। करुण क्रंदन से माहौल बेहद गमगीन हो गया। पांडे के परिजनों ने सरकार के लिखित आश्वासन के बगैर अंतिम संस्कार से इन्कार कर दिया था। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी एवं डीएम दीपेंद्र चौधरी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए रात में ही हल्द्वानी पहुंच गए थे। इस मामले में कांग्रेस एवं व्यापारिक संगठन राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बाजार बंद रखने का ऐलान कल ही कर चुके थे। हल्द्वानी में आज सुबह से ही दुकानों के ताले नहीं खुले है।

इधर तड़के से ही प्रकाश पांडे घर के पर लोग भी पहुंचने लगे है। शोकाकुल परिजनों ने आरोप लगाया कि जनता दरबार में प्रकाश की बात नहीं सुनी गई। उन्हें बाहर धकेलने को कहा गया। पति जहर खा चुके थे और वहां 1०8 का इंतजार होता रहा।शोकाकुल पत्नी कमला पांडे ने परिवार और बच्चों के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का लिखित आश्वासन न मिलने पर शव ना उठने देने की बात कह दी। मृतक ट्रांसपोर्टर व्यापारी प्रकाश पांडेय के आवास पर नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक डॉ. इंदिरा हृदयेश भी पहुंची। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। वहां मौजूद डीएम दीपेंद्र चौधरी व एसएसपी से उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवार के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पांडे की पत्नी को सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता दिए जाने के बावत सीएम से उन्होंने भी आग्रह किया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई आश्वासन नही दिया गया।उन्होंने कहा कि कारोबार न चलने व कर्ज से परेशान होकर प्रकाश ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। नोटबंदी ने ली एक और व्यापारी की जान ,सरकार के फैसलों पर सवालियां निशान काठगोदाम क्षेत्र में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा वहीं हल्द्वानी शहर के प्रमुख बाजारों में अधिकांश दुकानें बंद हैं। सदर बाजार, मीरा मार्ग, साहूकारा लाइन, मंगलपडाव में दुकाने बन्द हैं। कालाढूंगी मार्ग, बरेली रोड और मुखानी में ज्यादातर दुकानें खुली हैं। व्यापारियों की टोली बाजार बंद करा रही है। ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडेय की मौत पर व्यापारिक संगठनों की ओर से किये बाजार बंद का आंशिक असर दिख रहा है। काठगोदाम क्षेत्र में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा।

सीएम के खिलाफ हो हत्या का मुकदमा दर्ज: नेगी

विकासनगर/देहरादून। ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे द्वारा आर्थिक तंगी एवं सरकारी उदासीनता के चलते आत्महत्या मामले में जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रकाश पांडे की मौत व आत्महत्या मामले में जनसंघर्ष मोर्चा सीएम त्रिवेन्द्र रावत के खिलाफहत्या का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर सड़कों पर उतरेगा। यहां मोर्चा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि ट्राँसपोर्टर प्रकाश पांडे द्वारा आत्महत्या किये जाने का मुख्य कारण त्रिवेन्द्र सरकार की गलत नीतियाँ एवं अदूरदर्शिता है, जिसके चलते एक व्यवसायी को जहर खाने को मजबूर होना पड़ा। इस प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि प्रदेश का हर तबके का व्यक्ति इस सरकार की नीतियों एवं ढींगा मस्ती से परेशान है। उनका कहना है कि जब से त्रिवेन्द्र ने कुर्सी सम्भाली है सारे कारोबार ठप्प हो गये हैं।

नेगी ने आक्रोश जताते हुए कहा कि मोर्चा द्वारा त्रिवेन्द्र सरकार के भ्रष्टाचार एवं नकारेपन को लेकर लगातार हमला जारी है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। उनका कहना है कि त्रिवेन्द्र रावत की अनुभवहीनता एवं अदूरदर्शिता के चलते प्रदेश का व्यापारी, किसान, बेरोजगार, मजदूर सब हताश होकर बैठ गये हैं तथा अपने भाग्य को कोस रहे हैं। आलम यह है कि जब से इस निकम्मी सरकार ने कार्यभार सम्भाला है कोई व्यक्ति 2-4 हजार रूपये उधार लेने व देने की स्थिति में नहीं है। नेगी ने हैरानी जताई है कि भाजपा मुख्यालय में जहर खाने का पता लगते ही भाजपाईयों द्वारा प्रकाश पांडे को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि इन लोगों में संवेदनशीलता के लिए कोई जगह नहीं है।

जनसंघर्ष मोर्चा ने भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व को आगाह किया कि अभी भी समय है कि स्थिति सम्भाल लो वरना वो दिन दूर नहीं जब त्रिवेन्द्र रावत राज में हर रोज मौत के मेले लगेंगे। नेगी ने कहा कि प्रकाश पांडे की मौत व आत्महत्या मामले में जनसंघर्ष मोर्चा सीएम त्रिवेन्द्र रावत के खिलाफहत्या का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर सड़कों पर उतरेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में ओ पी राणा, चौधरी मामराज, रवि भटनागर, जाबिर हसन, मौहम्मद इस्लाम, फत्तेह आलिम, मदन सिंह, नत्थी सिंह पंवार, मनोज चौहान, कुंवर सिंह नेगी, जयदेव देगी, भीम सिंह बिष्ट आदि शामिल थे।

भाकपा माले का खुला आरोप

प्रकाश पांडे की मौत की जिम्मेदार सरकार

नैनीताल। भाकपा(माले) ने आज कार रोड, बिन्दुखत्ता बाजार में काठगोदाम के व्यापारी प्रकाश पाण्डेय की आत्महत्या के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा की त्रिवेन्द्र रावत सरकार का पूतला फूंका। इस दौरान हुई सभा को सम्बोधित करते हुए भाकपा(माले) के प्रदेश कमेटी सदस्य कॉमरेड पुरूषोत्तम शर्मा ने कहा कि नोटबन्दी और जीएसटी से परेशान होकर व्यवसायी की आत्महत्या की कोशिश और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण मौत सरकार की गलत नीतियों का दुष्परिणाम है। 127 करोड़ देशवासियों के अच्छे दिन लाने के वायदे करके जबसे मोदी जी केन्द्र की सत्ता में बैठे हैं तब से मुठठीभर गिने-चुने कॉरपोरेट घरानों व पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कभी नोटबंदी कभी जीएसटी जैसी नीतियां लागू कर रहे हैं। देश के मजदूर, किसान , व्यापारी नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से बर्बाद हो चुके हैं। नोटबंदी के समय 15० से ज्यादा लोग मारे गये, लाखों उद्योग धंधे बंद हो गये, लाखों लोग बेरोजगार हो गये। मोदी सरकार ने अम्बानी, अडानी जैसे अपने चंद चहेते पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने के लिए सरकारी खजाने से 2.11 लाख करोड़ रूपये बैंको को बैल आउट पैकेज के रूप में दे दिये। यदि यही पैसा किसान, मजदूर, व्यापारी आम जनता के शिक्षा , रोजगार, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने में खर्च किये जाते तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता, खेती, व्यापार आगे बढ़ता। लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण पहले तो लाखों किसान आत्महत्या कर चुके है और अब काठगोदाम के व्यापारी प्रकाश पाण्डे को भी आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा है। प्रदेश की त्रिवेन्द्र रावत सरकार के सामने उक्त व्यापारी ने बार -बार अपनी समस्याएं रखी। मगर राज्य सरकार ने समस्या का समाधान करने के बजाय आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। कॉमरेड पुरूषोत्तम शर्मा ने मांग की है कि मृत व्यापारी का पूरा कर्जा माफ हो, सरकार व्यापारी प्रकाश पाण्डेय की आत्महत्या की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा दे। पूतला फूंकने वालों में ललित मटियाली, पुष्कर दुबड़िया, हरीश भण्डारी, राजेन्द्र शाह, कमलापति जोशी, कल्लू मियां, खीम सिंह, कुन्दन बिष्ट समेत कई लोग शामिल थे।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक राजेश शर्मा द्वारा इंटर ग्राफिक प्रिंटर्स, 64-नेशविला रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड से मुद्रित, 142 श्रीदेव सुमन नगर बल्लूपुर रोड देहरादून से प्रकाशित।
सम्पादक : राजेश शर्मा मो.- 9897598151, **प्रबंध सम्पादक :** अभिषेक शाही मो.- 9897865003 कानूनी सलाहकार: प्रकाश टी पाल **E-mail ID:** crimestory.dial100@gmail.com नोट: समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन ही होंगे।